भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *205

उत्तर देने की तारीख 4 अगस्त, 2025

सोमवार, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक)

आईटीआई उन्नयन योजना

*205. सुश्री कंगना रनौतः

श्री गोडम नागेशः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई अनुमोदित राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उन्नयन योजना के मुख्य उद्देश्य और घटक क्या-क्या हैं और देश भर में अवसंरचना, पाठ्यक्रम और उद्योग सम्पर्क में सुधार के प्रस्तावित क्षेत्रों का जम्मू सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर जम्मू के लिए कुल कितना बजटीय आबंटन किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को निधियों के संवितरण हेतु क्या तंत्र है;

(ग) अनुमोदित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची और उनके बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) उत्तर-पूर्वी दिल्ली, मध्य प्रदेश के सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में उन्नयन हेतु पहचान किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ और राजस्थान विशेषकर जालौर और सिरोही सहित देश में कौशल विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्रों को मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"आईटीआई उन्नयन योजना" के संबंध में सुश्री कंगना रनौत और श्री गोडम नागेश द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *205 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और कौशल विकास हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. आईटीआई और एनएसटीआई में प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार अवसंरचना और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में, उद्योग-अनुरूप दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. माँग-आधारित कौशल विकास और बेहतर रोज़गार अवसरों के लिए उद्योग संपर्क को सुदृढ़ करना; और
v. प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता को बढ़ाना।

इस योजना के दो घटक हैं:

i. घटक I - 1,000 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (200 हब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 800 स्पोक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का हब और स्पोक मॉडल में स्तरोन्नयन करना। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्मार्ट कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल सामग्री और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करके इनका उन्नयन किया जाएगा।

ii. घटक II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित पाँच राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि करना, जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौशल विकास हेतु क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

इस योजना का कार्यान्वयन एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (एआईपी) की साझेदारी में गठित स्पेशल पर्पज व्हिकल्स (एसपीवी) के माध्यम से किया जाएगा ताकि कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता

और परिणाम-आधारित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। आईटीआई का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उद्योग के परामर्श से किया जाएगा। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, जम्मू और कश्मीर जैसे संघ राज्य क्षेत्रों सहित, समूचे भारत में कार्यान्वित की जाएगी।

(ख) इस योजना का कुल अनुमानित परिव्यय ₹ 60,000 करोड़ है, जिसमें पांच वर्ष की अवधि के दौरान केंद्र सरकार (₹ 30,000 करोड़), राज्य सरकारों (₹ 20,000 करोड़) और उद्योग भागीदारों (₹ 10,000 करोड़) का अंशदान शामिल है।

राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को उद्योग साझेदारी सहित रुचि और तैयारी के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। तदनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजटीय आबंटन किया जाएगा। निधि का संवितरण प्रत्येक क्लस्टर के लिए एआईपी द्वारा प्रस्तुत कार्यनीतिक निवेश योजनाओं (एसआईपी) के अनुमोदन के आधार पर होगा, जिसमें अवसंरचना, उपकरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन और प्रशिक्षण परिणामों का विवरण दिया जाएगा।

(ग) और (घ) आईटीआई का चयन और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजट आबंटन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा, जो उनकी तैयारी तथा उद्योग सहयोग के अध्यधीन होगा। उत्तर-पूर्वी दिल्ली, मध्य प्रदेश के सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) सहित आईटीआई के विशिष्ट समूहों पर, उद्योग भागीदारों के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के अंतर्गत कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र आईटीआई के अनुदेशकों और कार्मिकों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करेंगे, जिसके लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। ये केंद्र देश भर के आईटीआई के लिए उपलब्ध होंगे, और प्राप्त प्रस्तावों तथा योजना दिशानिर्देशों तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों जिनमें जालौर और सिरोही जैसे जिले शामिल हैं, में स्थित संस्थानों को भी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

*****